बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषयः– राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति।

[Approval for signing a memorandum of understanding (MoU) between Microsoft Corporation India Private Limited and Department of Information Technology, Bihar, Patna for development of Artificial Intelligence (AI) Ecosystem in the State.]

बिहार सरकार नये–नये तकनीकों का समावेश कर नवाचार के माध्यम से राज्य के विकास हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। राज्य को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना आवश्यक है।

2. माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 807, न्यू दिल्ली हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001 में स्थित है। भारत में स्थित विश्व की अग्रणी तकनीकी कंपनियों में से एक है, जो क्लाउड कम्प्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमता, मशीन लर्निंग, जेनरेटिव एआई एवं डिजिटल कौशल विकास में विश्व–स्तरीय विशेषज्ञता रखती है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच एक नीतिगत गैर–वित्तीय एवं गैर–बाध्यकारी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाने का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग करेंगे :–

- सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं Microsoft Corporation India Private Limited के बीच एक स्ट्रेटजिक कोलाबोरेशन फ्रेमवर्क स्थापित करना है, ताकि क्लाउड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती डिजिटल तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग के माध्यम से राज्य के डिजिटल परिवर्तन एजेंडे को सपोर्ट किया जा सके।
- राज्य में एक समावेशी और विश्वसनीय डिजिटल शासन को बढ़ावा देना।
- राज्य में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देना।
- सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढ़ाँचे का विकास करना जिससे राज्य में तकनीकी सशक्तीकरण हो सके।

क्रमशः 2/–

- नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाओं एवं सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना।
- Microsoft के तकनीकी प्लेटफॉर्म, वैश्विक विशेषज्ञता और नवाचार कार्यक्रमों का लाभ उठाना।

4. MoU में विभिन्न क्षेत्रों में Pilot परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है, जो प्राथमिकता निर्धारण, व्यवहार्यता मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहमति से क्रियान्वयन होगी। इनमें प्रमुखतः निम्नलिखित संकेतात्मक पहल सम्मिलित हैः—

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी अधिकारियों की डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहयोग किया जाएगा।
- डिजिटल कौशल, AI और क्लाउड तकनीकों से संबंधित प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु "ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स" मॉडल को सक्षम करने के लिए सहयोग करेंगे।
- राज्य सरकार के अन्तर्गत आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों, आई०टी०आई०, पॉलिटेकनिक एवं मेडिकल कॉलेजों के लिए विशेषीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पाठ्यक्रमों का डिजाइन और कार्यान्वयन करेगा।
- राज्य के स्टार्ट—अप हब और नवाचार कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव के माध्यम से बिहार के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे।
- राज्य के विभागों, एजेंसियों और सरकारी संस्थान में उपयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट (Microsoft Copilot), विंडोज डेस्कटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम सहित सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं को अपनाने और खरीद का मूल्यांकन करना।
- स्थानीय बिहारी भाषाओं में वॉयस और चौट—आधारित इंटरफेस ("Citizen Copilot") का उपयोग करते हुए AI—सक्षम नागरिक सहभागिता समाधानों के अन्वेषण और विकास हेतु सहयोग करेंगे।
- नागरिकों और सरकारी सेवाओं के बीच संवाद को सपोर्ट करने हेतु AI—सक्षम कॉल सेंटर क्षमताओं के डिज़ाइन और परिनियोजन पर सहयोग करेंगे।
- सरकार के डेटा की सुरक्षा तथा डिजिटल प्रणालियों की उपलब्धता, अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार के लिए सुरक्षित, resilient और विश्वसनीय डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने हेतु सहयोग करेंगे।
- ए.आई. आधारित कॉल सेंटर, नागरिक सेवाओं के लिए कॉल रूटिंग, स्पीच—टू—टेक्स्ट और ए.आई. असिस्टेड टूल्स से लैस आधुनिक कॉल सेंटर की रूपरेखा तैयार करना।
- राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए 'जीरो ट्रस्ट' सिद्धांत पर आधारित सुरक्षा प्रथाओं को लागू करना।
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 के तहत राज्य सरकार के Compliance एवं Operational readiness का सपोर्ट करने के लिए सहयोग करेंगे।

क्रमशः .....3/—

- नागरिकों और सरकारी प्रणालियों के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल विश्वास को बढ़ाने हेतु सहयोग करेंगे।

5. **प्रस्तावित समझौता ज्ञापन की प्रमुख शर्तें एवं विशेषताएँ निम्नवत् है :–**

- यह MoU गैर वित्तीय प्रकृति का है। इसके अंतर्गत किसी पक्ष पर कोई मौद्रिक दायित्व, वित्तीय प्रतिबद्धता, अनुदान, सब्सिडी अथवा बजटीय देनदारी सृजित नहीं होगी।
- यह MoU प्रभावी तिथि से 60 (साठ) माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
- दोनो पक्षों की गोपनीय सूचना की पूर्ण सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
- किसी भी विशिष्ट कार्यक्रम, पायलट परियोजना, क्रय अथवा अन्य पहल से उत्पन्न होने वाले वित्तीय दायित्वों हेतु पृथक निश्चित समझौता निष्पादित किए जाएंगे, जो दोनो पक्षों की प्रासंगिक अनुमोदन प्रक्रियाओं के अधीन होंगे।
- माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना, किसी भी वित्तीय दायित्व के लिए Definitive Agreement करेंगे एवं अलग से सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- MoU पर आधारित कोई भी समाचार विज्ञप्ति, सार्वजनिक घोषणा अथवा प्रचार–प्रसार दोनों पक्षों की पूर्व लिखित सहमति के बिना जारी नहीं की जाएगी।
- MoU भारत के कानूनों के अधीन शासित होंगे तथा किसी भी विवाद का निपटारा पटना स्थित न्यायालयों में किया जायेगा।

6. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. उक्त संकल्प को दिनांक 24.06.2026 को मद संख्या–28 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25/6/26

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 06–सू०प्रा०–22/2026 ......1189...... पटना, दिनांक ......25/6/26......

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष संस्करण में प्रकाशित करने के लिए। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियां मुद्रित करें तथा इस विभाग को उपलब्ध कराएं।

25/6/26

सरकार के सचिव।

क्रमशः 4/–

ज्ञापांकः 06—सू०प्रा०—22/2026 .....1189..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/6/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06—सू०प्रा०—22/2026 .....1189..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06—सू०प्रा०—22/2026 .....1189..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06—सू०प्रा०—22/2026 .....1189..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

25/6/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06—सू०प्रा०—22/2026 .....1189..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः— आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा सभी विभागों को e-mail के माध्यम से भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/26
सरकार के सचिव।